

वर्ष 2022-23 के बजट में बच्चों की हसिसेदारी

प्रलिस के लयल:

पोषण 2.0, पीएम ई-वदलया, 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' प्रोग्राम, एकीकृत बाल वकलस योजना, एनएफएचएस- 5 सरवे के नषिकरष ।

मेन्स के लयल:

भारत में बच्चों की स्थतल और उनसे संबधतल मुद्दों को संबोधतल करने की आवशयकता, इस दशल में सरकारों दवारा उठाए गए कदम ।

चरचा में क्यों?

हाल ही में एक गैर-सरकारी संगठन दवारा कयल गए वशल्लेषण के मुताबकल, बीते 11 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष देश में बच्चों को बजट में आवंटन का सबसे कम हसलसा प्राप्त हुआ है ।

- केंद्र सरकार दवारा बच्चों के लयल बजट बनाने की शुरुआत पहली बार वर्ष 2008 में बाल बजट ववलरण के प्रकाशन के साथ हुई थी । इसके बाद कई राज्यों ने भी इस कार्य को शुरु कयल है ।

बच्चों से संबधतल बजट में क्या शामिल है?

परचलय:

- वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में बच्चों के लयल कुल आवंटन 92,736.5 करोड़ रुपए है, जबकल पछले बजट में 85,712.56 करोड़ रुपए का आवंटन कयल गया था ।

- यदयपल यह नरलपेकष रूप से 8.19% की वृद्धल है, कतल यह केंद्रीय बजट में कुल वयय में वृद्धल के अनुपात में नहीं है ।

- बच्चों के लयल बजट का हसलसा इस वतलतीय वर्ष (2022-23) के लयल केंद्रीय बजट का केवल 2.35% है, यह 0.11% की कमी को दर्शाता है, जो कल पछले 11 वर्षों में बच्चों के लयल आवंटतल सबसे कम धनराशा है ।

कषेत्रवार वशल्लेषण:

बाल सवासुथय के लयल:

- बाल सवासुथय के लयल आवंटन में 6.08% की कमी की गई है ।

- सबसे महत्त्वपूर्ण बाल सवासुथय योजनाओं में से एक, NRHM-RCH फलेकसी पूल में 8.22% की कमी हुई है ।

- यह फलेकसी पूल राज्यों की सवासुथय प्रणालयों को मज़बूत करने के साथ-साथ प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं कशोर सवासुथय (RMNCH+A) की जरूरतों को पूरा करता है ।

बाल वकलस कार्यक्रम के लयल:

- अगले वतलत वर्ष के लयल आवंटन में 10.97% की गरलवट देखी गई है, जो 17,826.03 करोड़ रुपए है । इनमें पूरक पोषण और आंगनवाड़ी (डे केयर) सेवाएँ शामिल हैं ।

- महललाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान करने वाली पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को इस वर्ष कोई अतरकलत धनराशा आवंटतल नहीं हुई ।

- वर्ष 2022-23 में **प्रधानमंतरी पोषण शकतल नरलमाण (पीएम पोषण) कार्यक्रम** के लयल 10,234 करोड़ रुपए का अनुमानतल बजट स्वीकृत कयल गया है । पछले वर्ष संशोधतल अनुमान 10,234 करोड़ रुपए था ।

- इस योजना को पहले 'वदलयालयों में मधयाहन भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम' के रूप में जाना जाता था और इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के स्कूली बच्चों को गरम पका हुआ भोजन प्रदान कयल जाता था ।

बाल शकलषा के लयल:

- बाल शकलषा के लयल बजट का हसलसा चालू वतलत वर्ष में 1.74% से केवल 0.3% अंक की मामूली वृद्धल के साथ अगले वतलत वर्ष के लयल 1.73% हो गया है ।

- बजट में घोषतल 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम बच्चों के लयल सीखने का एक कठनल तरीका है ।

- पीएम ई-वदलया के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम का वसलतार 12 से 200 टीवी चैनलों तक कयल जाएगा ।

बच्चों के संरकषण और कलयाण के लयल:

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मशिन वात्सल्य के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं के लिये 1,472.17 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।
 - यह इस वित्त वर्ष की तुलना में 65% अधिक है, लेकिन योजना के पुनर्गठन से पहले 2019-2020 में 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन से कम है।

बच्चों के लिये बजट संबंधी मुद्दे:

- **मात्र वार्षिक लेखा अभ्यास:**
 - केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के लिये **बजट बनाना केवल एक वार्षिक लेखांकन अभ्यास** तक सीमिति रह गया है, जबकि बाल बजट वविरण (CBS) का प्रकाशन सभी विभागों में प्रासंगिक बजट शीर्षों को मिलाकर किया गया है।
 - यह अकेले बच्चों की विशेष ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी रहने के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिये बहुत कम है।
- **राज्य सरकारों में ज़िम्मेदारी की कमी:**
 - बच्चों के लिये कई महत्त्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने हेतु मुख्य रूप से ज़िम्मेदार होने के कारण राज्य सरकारें इस अभ्यास को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाती हैं।
 - लेकिन उनके द्वारा भी बच्चों के लिये अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाने और हस्तक्षेप हेतु एक उपकरण के बजाय इसे एक लेखांकन ज़िम्मेदारी के रूप में माना जाता है।
- **मानकीकरण का अभाव:**
 - इसके अलावा सरकारी संस्थाओं के बीच संबंधित बाल बजट वविरण (CBS) की रिपोर्टिंग हेतु मानदंडों के मानकीकरण की कमी है।

भारत में बच्चों की स्थिति:

- हाल ही में **NFHS-5 के सर्वेक्षण** में बाल स्वास्थ्य और पोषण पर मशरति तस्वीर सामने आई है।
 - एक तरफ इसके बाल मृत्यु दर में कमी, **पोषण संकेतकों के स्तर में सुधार जैसे स्टंटिंग और वेसटिंग** आदि निश्चित सकारात्मक पहलू हैं।
 - दूसरी ओर इस दौर में बच्चों में **एनीमिया** की घटनाएँ **NFHS 4 में 58.6% से बढ़कर 67.1%** के खतरनाक स्तर पर पहुँच गई हैं, प्रमुख विशेषज्ञों का कहना है कि **SDG लक्ष्य 2030** को पूरा करने के लिये और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
- **ASER सर्वेक्षण नषिकर्ष:**
 - लगातार **ASER सर्वेक्षणों** ने बताया है कि वर्ष 2020 और 2021 के बीच स्कूल में नामांकित बच्चों के अनुपात में कोई सुधार नहीं हुआ है और इस संबंध में **राज्यों के बीच बहुत अधिक परिवर्तनशीलता** है।
- **कोविड-19 का प्रभाव:**
 - कोविड-19 ने बच्चों को विधि तरीकों से प्रभावित किया है चाहे वे शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक या सामाजिक प्रभाव हों, इसमें शामिल हैं- संक्रमण या प्रवास, पारिवारिक संकट, दोस्तों से अलगाव, सीखने की प्रक्रिया में बाधा, पर्यावरण, स्वयं या परिवार के सदस्यों का अस्पताल में भर्ती होना, कार्य में वयस्कों की भूमिका या फरि विवाह।
 - कोविड-19 ने भारत में बच्चों की शिक्षा, पोषण और विकास तथा बाल संरक्षण तक उनकी पहुँच को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया था।

आगे की राह

- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों से संबंधित हस्तक्षेपों पर कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों का अनुमुखीकरण न केवल CBS में रिपोर्टिंग के लिये बल्कि उन्हें योजनाओं को पुनः बेहतर ढंग से डिज़ाइन करने तथा नियमि आधार पर उनकी प्रगति की नगिरानी करने में सक्षम बनाने हेतु भी महत्त्वपूर्ण है।
- परवियों को बेहतर परिणामों में परिवर्तित करने हेतु बच्चों के लिये बजट का एक परिणाम अभविन्यास आवश्यक है।
- CBS में रिपोर्टिंग संरचना को मानकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता है तथा केंद्र सरकार CBS को जवाबदेही का एक प्रभावी साधन बनाने के लिये राज्यों और विशेषज्ञों के परामर्श से इसके लिये एक वसितुत ढाँचा विकसित कर सकती है।
- संबंधित मंत्रालयों द्वारा बाल संबंधित योजनाओं की नियमि नगिरानी और लेखापरीक्षा की जानी चाहिये।

स्रोत: द हट्टू